



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1981/अग्रहायण 2, 1903

No. 377] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1981/AGRAHAYANA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1981

प्रायक

सं० का० मि० 612(अ):—दोहरे कराधान से बचने के लिए और
घाय और पूंजी अभिलाषों पर करों की वास्तविक वित्तीय अपवर्धन के
निवारण के लिए भारत सरकार और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड
की यूनाइटेड किंगडम के बीच इससे उपावह करनेकाम, जैसा कि उक्त
कन्वेंशन के अनुच्छेद 27 द्वारा अपेक्षित है, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा
अपनी-अपनी विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूरी कर लेना, एक दूसरे को अधि-
सूचित कर देने पर, प्रवृत्त हो गया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, घाय कर अधिनियम, 1961 (1961 का
43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964
(1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबन्धों को भारत
संघ में प्रभावी किया जाएगा।

981 GI/81—1

भारत सरकार

घोर

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्थ आयरलैंड

की सरकार

के बीच घाय तथा पूंजीगत लाभ पर दोहरे कराधान
के परिहार और राजस्व अपवर्धन को रोकने के लिए

अभिसमय

भारत सरकार

घोर

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्थ आयरलैंड

की सरकार

के बीच

घाय तथा पूंजीगत लाभ पर दोहरे कराधान के परिहार
और राजस्व अपवर्धन को रोकने के लिए अभिसमय

भारत की सरकार और यूनाइटेड किंगडम आफ
ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्थ आयरलैंड की सरकार
घाय तथा पूंजीगत लाभ पर करों के सम्बन्ध में दोहरे

(1769)

कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्धन को रोक्ने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से,
नीचे निम्ने अनुसार महमन हुई है

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक प्रथम दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1 यह अभिसमय जिन करों पर लागू होगा वे हैं:

(क) 'यूनाइटेड किंगडम फ्रॉक प्रेंट ब्रिटेन एण्ड नार्थ आयरलैंड' में:

- (i) धार कर,
- (ii) निधम कर;
- (iii) पूंजीगत लाभ कर;
- (iv) पेट्रोलियम राजस्व कर; और
- (v) विकसित भू-कर;

(जिन्हें इसके बाद "यूनाइटेड किंगडम कर" कहा जाएगा)

(ख) भारत में:

- (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला आयकर जिसमें उस पर लगाया जाने वाला प्रत्येक अधिभार भी शामिल है;
- (2) कम्पनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अधिकार (जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)

2. यह अभिसमय वर्तमान करों प्रथम उनकी जगह धराए जाने वाले करों के अतिरिक्त समरूप प्रथम सारतः जैसे ही करों पर भी लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर हो जाने की तारीख के बाद किसी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं परिवर्तनों के सम्बन्ध में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परनिष्ठाएं

1 इस अभिसमय में, जब तक सन्ध में अन्यथा प्रवेक्षित न हो

(क) 'यूनाइटेड किंगडम' पद का अर्थ होगा ब्रिटिश तथा नार्थ आयरलैंड जिसमें यूनाइटेड किंगडम की समुद्री सीमा से बाहर का ऐसा कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार महाद्वीपीय शील्ड से सम्बन्धित यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के अन्तर्गत आता हो या बाद में आ जाए जिस पर समुद्री-तल तथा भू-गर्भ और उनके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में यूनाइटेड किंगडम के अधिकारों का प्रयोग किया जाए;

(ख) 'कर' पद से, सर्वश्रेष्ठ की प्रथम के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम का कर प्रथम भारतीय कर अभिप्रेत है;

(ग) भारतीय कर के सम्बन्ध में "राजस्व बर्ष" का अर्थ भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में वषा परिभाषित "पिछला बर्ष" है,

(घ) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" पद से अभिप्रेत होगा यूनाइटेड किंगडम प्रथम भारत और सर्वश्रेष्ठ से अभिप्रेत हो;

(ङ) "व्यक्ति" पद से अभिप्रेत होगा—कोई व्यक्ति, कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय;

(च) "कम्पनी" शब्द से कोई ऐसा निगमित निकाय प्रथम कोई इकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए कम्पनी प्रथम निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पद से क्रमशः संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत होगा;

(ज) यूनाइटेड किंगडम के मामले में "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत होगा, आन्तरिक राजस्व के आयुक्त प्रथम उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार का राजस्व विभाग;

(झ) "अन्तर्राष्ट्रीय मातायात" पद से अभिप्रेत होगा किसी ऐसे जलयान प्रथम वायुयान द्वारा परिवहन जो ऐसे किसी उद्यम द्वारा संचालित को जिसकी प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान किसी संविदाकारी राज्य में हो, सिवाय उस स्थिति के जब कि जलयान प्रथम वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के ही स्थानों के बीच चलया जाता हो;

(ञ) "सरकार" पद से अभिप्रेत होगा किसी संविदाकारी राज्य प्रथम उसका राजनीतिक उपविभाग प्रथम स्थानीय प्राधिकरण की सरकार। यूनाइटेड किंगडम के मामले में "राजनीतिक उप विभाग" में नार्थ आयरलैंड शामिल होगा।

2 जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, किन्तु पद का, जो प्रथम परिभाषित नहीं हुआ हो, सर्वश्रेष्ठ में जब तक प्रथम न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

1 इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत होगा कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर वहाँ, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान प्रथम इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है।

2 जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसका वर्ग नीचे लिखे नियमों के अनुसार तय किया जाएगा।

(क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका स्थायी घर हो। यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी घर है तो वह उन संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध अनिवार्य हैं (महत्वपूर्ण द्रव्यों का केन्द्र);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय न किया जा सकता हो, प्रथम यदि उसकी किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास उपलब्ध न हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह प्रामाण्य से रहता हो,

- (ग) यदि वह आमतौर से दोनों ही संविदाकारी राज्यों में रहता हो प्रथम उनमें से किसी भी राज्य में सीमांतरी से न रहता हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक हो प्रथम उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक न हो तो संविदाकारी राज्यों के सभ्य प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3 जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण से, व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रभावी प्रवास का स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद 5

स्वायी स्थापन

1. इस अधिसूचन में "स्वायी स्थापन" पद का अर्थ होगा कारोबार का वह निश्चित स्थान जहां उद्यम का कारोबार पूर्णतः प्रथम प्रस्थापित किया जाता है ।

2 "स्वायी स्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई भाड़ा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई परिसर जहां से विक्रय-कार्य किया जाता हो और जहां विक्रय प्रारंभ प्राप्त किए जाते हों ;
- (छ) जो व्यक्ति दूसरों को भंडारण की सुविधायें देता हो उसका कोई मास गोदाम ;
- (ज) कोई खान, कुली खान प्रथम ऐसा कोई अन्य स्थान जहां से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हों ;
- (झ) प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई संस्थापन प्रथम संरचना ;
- (ञ) कोई भवन-निर्माण प्रथम निर्माण, संस्थापन प्रथम संयोजन परियोजना प्रथम उसके सम्बन्ध पर्यवेक्षी कार्यवाही जहां इस प्रकार का स्थान, परियोजना प्रथम पर्यवेक्षी कार्यवाही छः महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती है प्रथम जहां इस प्रकार की परियोजना प्रथम पर्यवेक्षी कार्यवाही, मशीनरी प्रथम उपस्करों के विक्रय से सम्बन्ध रखती हो और छः महीने से अधिक अवधि तक जारी न रहे और उस परियोजना प्रथम पर्यवेक्षी कार्यवाही के लिए वेय प्रभार मशीनरी और उपस्कर के बिक्री मुख्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो ;

3. "स्वायी स्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा ;

- (क) किसी उद्यम के मास प्रथम तिजारती सामान के पूर्णतः भंडारण प्रथम उसके प्रवेश के उद्देश्य से किन्हीं सुविधायों का प्रयोग ;
- (ख) केवल भंडारण प्रथम प्रवेश के उद्देश्य से उद्यम के मास प्रथम तिजारती सामान का स्टॉक रखना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित करने के उद्देश्य से ही उद्यम के मास प्रथम तिजारती मास का स्टॉक रखना ;

(घ) किसी उद्यम के लिए मास प्रथम तिजारती मास खरीद प्रथम सूचना एकत्र करने के उद्देश्य मास के लिए ही व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान रखना ;

(ङ) केवल बिहापन के लिए सूचना देने के लिए प्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से ही, जो सम्बन्ध उद्यम के व्यापार में पूर्णतः आरम्भिक प्रथम सहायक स्वरूप की गतिविधियां ही होती हैं, व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान रखना लेकिन अगर सम्बन्ध उद्यम इस पैराग्राफ में बताये गये उद्देश्यों से अगर किसी उद्देश्य प्रथम उद्देश्यों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यवसाय का कोई अन्य निश्चित स्थान रखता हो तो यह प्राधान्य उस पर लागू नहीं होगा ।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए प्रथम उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति की स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न ही ओर जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो—प्रथमोक्त राज्य में उद्यम का स्थायी स्थापन माना जाएगा, यदि ;

- (क) उद्ये आमतौर पर उस राज्य में उस उद्यम के लिए और उद्यम की ओर से बातचीत करने का तथा उसके लिए प्रथम उद्यम की ओर से संबन्ध सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर पर उस अधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसकी गतिविधियां उस उद्यम के लिए मास प्रथम सामान खरीदने तक ही सीमित न हों ; प्रथम
- (ख) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में आमतौर से उस उद्यम के मास प्रथम तिजारती मास का भण्डार रखता हो जिसमें से वह उस उद्यम के लिए प्रथम उद्यम की ओर से मास प्रथम तिजारती मास नियमित रूप से भेजता हो ।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा कि वह किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट प्रथम स्वतंत्र हैसियत के किसी अन्य एजेंट के माध्यम से उस दूसरे राज्य में कारोबार करता है जहां उपर्युक्त प्रकार के व्यक्ति इस तरह का कारोबार सामान्यतः करते हों ; लेकिन यदि इस प्रकार के एजेंट की कार्यवाहियां पूर्णतः प्रथम लगभग पूर्णतः उस उद्यम विशेष के लिए की जाती हों (प्रथम इस उद्यम प्रथम ऐसे अन्य उद्यमों के लिए की जाती हों जो उक्त उद्यम विशेष के द्वारा नियंत्रित हों प्रथम इसमें उसके नियंत्रणकारी हित हों) तो उसे इस पैराग्राफ के प्रयोजन से स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा ।

6. यदि कोई कम्पनी जो किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी कम्पनी को नियंत्रित करती हो प्रथम उससे नियंत्रित होती हो प्रथम जो उस दूसरे राज्य में कारोबार करती हो (वाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से प्रथम प्रथम) तो मास इस तथ्य के लिए हो उन दोनों में से किसी को दूसरे का स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद 6

प्रथम सम्पत्ति से आय

1. प्रथम सम्पत्ति से आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जायेगा जिसमें इस प्रकार की सम्पत्ति स्थित है ।

2. (क) इस पैराग्राफ के उप पैरा (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत हुए "प्रथम सम्पत्ति" पद उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार परिभाषित किया जायेगा जहां सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है ।

(ख) "प्रथम सम्पत्ति" पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे प्रथम सम्पत्ति के उप सामान के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-सम्पत्ति में प्रयुक्त वस्तुसम तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर प्रथम सम्पत्ति सम्बन्धी

सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, जबकि सम्पत्ति की भोगने के अधिकार और कनिष्ठ भन्सार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिकूल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अवायगियों के अधिकार / श्रोत तथा विमान अथवा सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अथवा सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये से अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धाय पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की अथवा सम्पत्ति से प्राप्त धाय पर और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन में प्रयुक्त अथवा सम्पत्ति से प्राप्त धाय पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन द्वारा कारोबार न करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो दूसरे राज्य में उद्यम के लाभों पर कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उतने भंश पर ही कर लगेगा जो कि उस स्थायी स्थापन से सम्बन्धित है।

2. यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी स्थापन द्वारा कारोबार करता हो, अथवा संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी स्थापन का ही नाम पर न लाया जायेंगे जो कि उसके द्वारा प्राप्त होने की तब अथवा उन्हीं या वैसे ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है, जिसका यह एक स्थायी स्थापन है।

जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में उसके कानून के अनुसार किसी उद्यम के कुल लाभ के उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापन को होने वाले लाभ को निर्धारित करना प्रचलित रहा हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के द्वारा वह संविदाकारी राज्य, प्रचलित तरीके से ऐसे प्रभाजन से लाभ पर कर निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रभावित न होगा, परन्तु प्रभाजन के प्रयोग का तारीक, ऐसा होगा कि परिणाम, इस अनुच्छेद में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

4. (क) स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में व्ययों की कटौतियों को स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें केवल इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यथा और जिनकी स्वीकृति उस संविदाकारी राज्य के अपने प्राकृतिक कानून के उपबन्धों के अंतर्गत की जाती है, जहां स्थायी स्थापन स्थित है। परन्तु जहां उस संविदाकारी राज्य के कानून द्वारा, स्वीकार्य कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय राशि पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जहां स्थायी स्थापन स्थित है, और उस संविदाकारी राज्य और किसी तीसरे राज्य के बीच किसी अभिसमय के फलस्वरूप उस में कूट हो जाती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, और जोकि इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद प्रवृत्त होगा, उस संविदाकारी राज्य का कोई स्वयं अधिकारी अन्य संविदाकारी राज्य के समान अधिकारी को उस अभिसमय के लागू होने के दुरस्त बाद, उस तीसरे राज्य के साथ हुए अभिसमय के तत्वरूप पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तों के बारे में अधिसूचित करेगा, और अन्य संविदाकारी राज्य के समान अधिकारी के अनुरोध करने पर इस उपपैराग्राफ के उपबन्धों में प्रोटोकॉल द्वारा संशोधन किया जाएगा, जिसमें ऐसी शर्तों का उल्लेख होगा।

(ख) तथापि, स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय का अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले स्वामित्व, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अवायगियों के रूप में, अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध के लिए कर्मगण के रूप में अथवा, बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी स्थापन को उधार किये गए धन पर व्याज के रूप में, यदि कोई एकमें अथवा की गई हों, तो उन के सम्बन्ध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं की जायेगी। इसी प्रकार, स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा, जो स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय की या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), स्थायी स्थापन द्वारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अवायगियों के रूप में अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबन्ध के लिए कर्मगण के रूप में अथवा, बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किसी अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिये गए धन पर व्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रसारित की गई हो।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुया नहीं माना जाएगा, कि उस स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या अन्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. जहां लाभों में धाय की वे मर्बें शामिल हों, जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेक्षित किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध, इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तराष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त धाय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जायेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध इसी तरह विमान परिवहन में लगे उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के पुलों में भाग लेने के सम्बन्ध में लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए :

(क) अन्तराष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से सम्बन्ध विधियों पर व्याज को ऐसे वायुयान संचालन से होने वाली धाय माना जायेगा ; और

(ख) "वायुयान संचालन" पद में सम्मिलित होगा वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अग्रेताओं बाटेर (से) द्वारा वायुयान के जरिये किया जाने वाला व्यक्तियों, पशुधन, माल अथवा डाक का परिवहन कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की तरफ से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आनुपंगिक, पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध अन्य कार्य शामिल हैं।

4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को उस उद्यम के स्वामित्व के और उस उद्यम द्वारा संचालित वायुयान के हस्तांतरण से प्राप्त लाभों पर, जिससे हुई धाय केवल उस राज्य में कर लगे योग्य है, केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

अनुच्छेद 9

जहाजराशि

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की, अन्तराष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से होने वाली धाय पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी ऐसी भाग पर उस अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जहाँ से वह भाग प्राप्त होती है, बशर्ते :

(क) उक्त भाग, इस अभिसमय के प्रवर्तनकाल के प्रथम दस वित्तीय वर्षों के किसी एक अथवा अधिक वर्षों से सम्बन्धित हो ;

(ख) उस भाग पर प्रभाय कर, उस कर का 50 प्रतिशत होगा, जो इस अभिसमय के प्रवर्तनकाल के प्रथम पाँच वित्तीय वर्षों की भाग के सम्बन्ध में इस अभिसमय के अभाव में प्रभाय होता और अगले अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिये ऐसे कर का 25 प्रतिशत होगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध ऐसे स्थानों के बीच की यात्राओं से होने वाली भाग पर लागू नहीं होंगे, जो किसी संविदाकारी राज्य में स्थित हों ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ पोतों के संचालन से होने वाली भाग में, रिक्त पोत आधार पर पोतों से सम्बन्धित किराये से होने वाली भाग भी शामिल है, यदि किराये से हुई ऐसी भाग, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में वर्णित भाग की भागवर्गिक भाग हो ।

5. अनुच्छेद 7 (कारबारलाभ) के उपबन्धों के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबन्ध, संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की, माल अथवा पण्य के परिवहन के लिये प्रयुक्त कन्टेनरों (कन्टेनरों के परिवहन के लिये ट्रेलरों और सम्बन्धित उपस्कर सहित) के इस्तेमाल, रखरखाव अथवा किराये से हुई भाग पर इसी प्रकार लागू होंगे ।

6. इस अनुच्छेद के उपबन्ध, किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा अंतर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाली भाग पर भी लागू होंगे ।

7. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को, उक्त उद्यम द्वारा अपनी मालिकी के तथा प्रचालित पोतों अथवा कन्टेनरों के हस्तांतरण से प्राप्त मुनाफों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जावेगा यदि हस्तांतरित पोतों अथवा कन्टेनरों के संचालन से हुई भाग पर कर केवल या तो उसी राज्य में लगाया गया हो अथवा हस्तांतरण के समय पोत अथवा कन्टेनर अन्य संविदाकारी राज्य के बाहर स्थित हो ।

अनुच्छेद 10

सम्बन्धित उद्यम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूँजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं, जो वंसी शर्तों से भिन्न हैं जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उक्त उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और वे तदनुसार कराये जा सकेंगे ।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. (क) यूनाइटेड किंगडम की निवासी किसी कम्पनी द्वारा भारत के किसी निवासी को भुगत किये गये लाभांश पर भारत में कर लग सकता है ।

(ख) जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत भारत का कोई निवासी उस लाभांश के सम्बन्ध में कर जमा का हकदार हो, वहाँ, लाभांश की कुल रकम अथवा मूल्य पर और कर जमा की रकम पर, 15 प्रतिशत से अधिक की दर पर, यूनाइटेड किंगडम में भी और यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है ।

(ग) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (ख) में किये गये उपबन्ध के अलावा, भारत के किसी ऐसे निवासी द्वारा जो लाभांश का लाभकारी स्वामी हो, यूनाइटेड किंगडम की किसी निवासी कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर यूनाइटेड किंगडम में ऐसे किसी भी कर से छूट प्राप्त होगी जो लाभांशों पर प्रभाय हो ।

2. भारत का कोई निवासी, जो किसी ऐसी कम्पनी से लाभांश प्राप्त करता हो जो यूनाइटेड किंगडम की निवासी हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन और बशर्ते वह लाभांश का लाभकारी स्वामी हो, उस लाभांश के सम्बन्ध में कर जमा का हकदार होगा जिसका हकदार कि यूनाइटेड किंगडम में कोई व्यक्ति निवासी उस स्थिति में हुआ होता जब उसे वह लाभांश प्राप्त हुआ होता, और यूनाइटेड किंगडम के कर की देनदारी से अधिक की उस कर जमा को किसी धितरित अवायगी का हकदार होगा ।

3. इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 2 उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब लाभांश की लाभकारी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी हो जो या तो अकेले ही अथवा एक या एक से अधिक सम्बन्धित कम्पनियों के साथ मिलकर लाभांश की अवायगी करने वाली कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत मत देने की शक्ति को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित करती हो । इस प्रयोजन के लिए वे कम्पनियों को सम्बन्धित माना जावेगा यदि वे एक दूसरी से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित होती हैं, अथवा दोनों ही किसी तीसरी कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित होती हैं ।

4. भारत की निवासी किसी कम्पनी द्वारा यूनाइटेड किंगडम के किसी निवासी को भुगत किये गये किसी लाभांश पर यूनाइटेड किंगडम में कर लग सकता है । लाभांश पर भारत में भी कर लग सकता है परन्तु, जहाँ, लाभांश पूर्णतः अथवा अंशतः किसी गये अंशदान से सम्बन्धित हो, वहाँ इस प्रकार लगाये गये भारतीय कर की रकम गये अंशदान के कारण प्राप्त लाभांश की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफ उस कम्पनी से सम्बन्धित काराधान अवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे जिसके लाभों के सम्बन्ध में लाभांश की अवायगी की जाती है ।

6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 3 अथवा, जैसी भी स्थिति हो, पैराग्राफ 4 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जब लाभांश के लाभकारी स्वामी का, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण ऐसे अन्य संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश की अवायगी करने वाली कम्पनी निवासी हो, कोई ऐसा स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार हो जिससे वह नियंत्रक कम्पनी जिसके कारण लाभांश की अवायगी की जाती है प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो । इस तरह के मामलों में अनुच्छेद 7 (कारबार से लाभ) अथवा अनुच्छेद 18 (स्वतंत्र वाणिज्यिक सेवाएँ) के उपबन्ध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

7. जहाँ कोई ऐसी कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ भ्रषवा प्राय प्राप्त करती हो, वहाँ वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा भ्रषा किए गए लाभों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहाँ तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी की जिम्मेदारी सम्बन्ध कम्पनी के लाभों पर नहीं किए जाते भ्रषवा जहाँ तक कि नियंत्रक कम्पनी जिसके सम्बन्ध में लाभों भ्रषा किए जाते हैं उस अन्य राज्य में स्थित एक स्थायी स्थापन भ्रषवा एक निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बन्ध नहीं है भ्रषवा कम्पनी के प्रतिष्ठित लाभों पर प्रतिष्ठित लाभों सम्बन्धी कर नहीं लगाया जाएगा चाहे भ्रषा किए गए लाभों भ्रषवा प्रतिष्ठित लाभपूर्ण रूप से भ्रषवा प्राधिकार रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ भ्रषवा प्राय के रूप में हो हों।

8. जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, "लाभों" शब्द का अर्थ है शेरों से भ्रषवा अन्य अधिकारों से हुई प्राय, जो जून-वाले नहीं हैं लाभों में सम्मिलित हों, तथा उस राज्य के कराधान कानून द्वारा शेरों से हुई प्राय की तरह मानी गई अन्य निर्धारित अधिकारों से प्राप्त हुई प्राय है जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है और (अनुच्छेद 12 के उपबन्धों के अन्तर्गत जाने वाले व्याज से भिन्न) ऐसी कोई अन्य मद है जिसे कानून के अन्तर्गत लाभों भ्रषवा वितरण समझा गया हो।

9. जैसा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में प्रयुक्त है, "नया वितरण" पद का अर्थ है बोनस शेरों से भिन्न ऐसी कोई शेर पूंजी जो भारत की किसी निवासी कम्पनी द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन की तारीख के बाद जारी की गई और यूनाइटेड किंगडम के किसी निवासी द्वारा लाभकारिता के साथ अपने स्वामित्व में रखी गई हो।

अनुच्छेद 12

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भ्रषा किये जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, ऐसे व्याज पर, उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिसमें यह उत्पन्न होता है, किन्तु जहाँ दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी व्याज का लाभकारी स्वामी है और इसे अभिसमय की प्रवर्तन की तारीख के बाद पहले जारी किये गये उधार भ्रषवा जून के सम्बन्ध में भ्रषा किया जाता है तो इस प्रकार लगाया गया कर, व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबन्धों के रहते हुए भी

(क) जहाँ व्याज, वास्तविक बैंकिंग कारोबार चला रहे किसी बैंक को भ्रषा किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है और व्याज का लाभकारी स्वामी है, तो उस संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न होता है लगाया गया कर व्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ख) जहाँ व्याज, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की सरकार भ्रषवा उस राज्य के किसी राजनैतिक उप मण्डल भ्रषवा स्थानीय प्राधिकरण भ्रषवा भारतीय रिजर्व बैंक को भ्रषा किया जाता है तो उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा जिसमें यह उत्पन्न होता है।

4. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "व्याज" शब्द के अधिशेष अर्थों प्रकार के कर्ज सम्बन्धी लाभों से प्राप्त प्राय चाहे वे बंधन द्वारा प्रतिष्ठित हों भ्रषवा नहीं और चाहे उनको जूनवाला के लाभों में भागीदार का अधिकार प्राप्त हो भ्रषवा नहीं, और ब्याज पर सरकारी प्रतिभूतियों

से प्राप्त प्राय और बंधनवर्ती भ्रषवा जून-पत्रों जिन में ऐसी प्रतिभूतियों, बंधनवर्ती भ्रषवा जून-पत्रों के सम्बन्ध में प्रधान किये जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त प्राय से है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबन्ध उन स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का लाभकारी स्वामी किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता हो भ्रषवा उस दूसरे राज्य में उसमें स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो और जिस जून-पत्र के बारे में व्याज भ्रषा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान भ्रषवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) भ्रषवा अनुच्छेद 13 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि व्याज भ्रषा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-मण्डल, कोई स्थानीय प्राधिकारी भ्रषवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज भ्रषा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो भ्रषवा नहीं, कर्जदारी के सम्बन्ध में संविदाकारी राज्य में उसका स्थायी प्रतिष्ठान भ्रषवा निश्चित स्थान है, और उस कर्जदारी पर व्याज की भ्रषावर्गी की जाड़ी है, और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान भ्रषवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान भ्रषवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ व्याज, भ्रषा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच भ्रषवा कुछ व्यक्तियों के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण भ्रषा की गई व्याज की रकम, किसी भी कारण से उस रकम से बढ़ जाती है, जो इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में भ्रषा की गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल प्रतिभूत वणिज रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भ्रषावर्गियों के अधिभाग पर, इस अभिसमय के अन्य उप-बन्धों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ और शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए भ्रषा की गई रायल्टियों और शुल्कों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों और शुल्कों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उत्पन्न होती हैं; बशर्त कि जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ और शुल्क अन्य संविदाकारी राज्य के ऐसे निवासी को भ्रषा किए जाते हों जो उनका लाभकारी स्वामी हो और इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद पहले प्रधान किए गए अधिकार भ्रषवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रषा किए जाते हों भ्रषवा किसी संविदा के अन्तर्गत हस्ताक्षर किए जाते हों, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रायल्टियों और शुल्कों को सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द से—

(क) कोई पेटेंट, ड्रेडमार्क, डिजाइन भ्रषवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला भ्रषवा प्रक्रिया;

(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक भ्रषवा वैज्ञानिक उत्स्कर्क भ्रषवा औद्योगिक, वाणिज्यिक भ्रषवा वैज्ञानिक अनुभव के सम्बन्धित जानकारी;

(ग) कोई सांविधिक कलात्मक अथवा वैज्ञानिक क्रियाएँ उत्पन्न करने के लिये तथा ऐश्वर्य प्रथम रूप से प्रकाशित करने के लिये किन्हीं प्रयत्नों में ;

के प्रयोग के लिए प्रथम प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की प्रदायगी अभिप्रेत है किन्तु इसमें जातीय प्रथमता के कार्यपालन अथवा प्राकृतिक साधनों के निकालने अथवा हटाने के सम्बन्ध में प्रदा की गई रायल्टियाँ अथवा अन्य रकमें सम्मिलित नहीं हैं ।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों" पर से प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वयं की सेवाओं के, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कामों की सेवाओं की व्यवस्था सम्मिलित है, प्रतिकूल में प्रदायगियाँ करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी की प्रदायगियाँ करने तथा अनुच्छेद 15 में (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ) वर्णित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को की गयी प्रदायगियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रदायगियाँ अभिप्रेत हैं ।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 का उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा शुल्कों का लाभकारी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ तथा शुल्क उद्भूत होते हैं, वहाँ पर स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा वहाँ पर स्थित स्थायी स्थापन के उस अन्य राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ करता है जिससे अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ अथवा शुल्क प्रदा किए जाते हैं, ऐसे स्वामी स्थापन अथवा निश्चित आधार के साथ कारगर रूप से सम्बन्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबन्ध (कारोबार से लाभ) अथवा अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ), यथावस्था, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ और शुल्क उद्भूत हुए माने जायेंगे, यदि रायल्टियाँ और शुल्क प्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ अथवा शुल्क प्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार हो जिससे सम्बन्ध में प्रदायगियाँ करने का इकरारनामा किया गया हो और उस स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा प्रदायगियाँ की जाती हों, तब तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियाँ अथवा शुल्क उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए माने जाएंगे जिसमें स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है ।

7. जहाँ, रायल्टियाँ अथवा शुल्क प्रदा करने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए प्रदा की गयी रायल्टियाँ अथवा शुल्कों की रकम, उस रकम से किसी भी कारण से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में यह रकम प्रदा की गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । उस मामले में प्रदायगियों के प्रतिरिक्त भंड पर इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायगा ।

अनुच्छेद 14

पूँजीगत लाभ

इस अधिसमय के अनुच्छेद 8 (विमान-परिवहन) और अनुच्छेद 9 (अज्ञातकारी) में यथा उपबंधित की छोड़ कर, प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने देश के कानून के उपबन्धों के अनुसार पूँजीगत लाभों पर कर लगा सकता है ।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, वृत्ति सम्बन्धी सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्राप्त आय पर उस राज्य में कर लग सकेगा । अन्य संविदाकारी राज्य में ऐसी आय पर कर लगाया जा सकेगा यदि ऐसी सेवाएँ उस अन्य राज्य में की जाती हैं और यदि :

(क) संगत वित्तीय वर्ष में कुल 90 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए वह उस अन्य राज्य में उपस्थित रहा हो ; अथवा

(ख) अपने कार्यकलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो ;

किन्तु केवल प्रत्येक मामले में ही उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो इन सेवाओं के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हों ।

2 "वृत्ति सम्बन्धी सेवाएँ" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, सांविधिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, सर्जनों, बकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएँ

1. अनुच्छेद 17 (निदेशक शुल्क), 18 (कलाकार और खिलाड़ी), 19 (सरकारी पारिश्रमिक और पेन्शनें), 20 (विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी) और 21 (अध्यपक) के उपबन्धों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, ब्रिटेन के निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक पर भारत में प्रयुक्त नियोजन के सम्बन्ध में भारत में कर नहीं लगेगा यदि :-

(क) वह संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिला कर 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए भारत में मौजूद रहा है ;

(ख) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी हो, जो भारत का निवासी नहीं है ; और

(ग) भारतीय कर लगने योग्य किसी उपक्रम के लाभों का हिसाब लगाते समय पारिश्रमिक कटौती योग्य नहीं है ;

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, भारत के निवासी को, संयुक्त राज्य में प्रयुक्त नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर यूनाइटेड किंगडम में नहीं लगेगा यदि :-

(क) वह किसी संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए यूनाइटेड किंगडम में रहा हो ;

(ख) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई हो जो यूनाइटेड किंगडम का निवासी नहीं है ; और

(ग) यूनाइटेड किंगडम के कर लगने योग्य किसी उपक्रम के लाभों का हिसाब लगाते समय, पारिश्रमिक कटौती योग्य नहीं है ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा, जिसका, जलपोत अथवा वायुयान संचालन से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति निवास है।

अनुच्छेद 17

शिक्षक श्रृंखला

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की भवयुक्तियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) और 16 (पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं) के उपबन्धों के होते हुए भी मनोरंजन कलाओं (जैसे रंगमंच, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार और संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हैसियत से अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त भाग पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में अपनी हैसियत से किये गये वैयक्तिक कार्यों से उद्भूत भाग उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्रोद्भूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, ऐसे मामले में उस पर, अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ), 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) और 16 (पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं) के उपबन्धों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ और में उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा उक्त खिलाड़ी की, संविदाकारी राज्य की यात्रा का ध्येय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की, जिसमें दूसरे राज्य का राजनीतिक उप-मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सरकारी निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः किया गया हो।

अनुच्छेद 19

सरकारी पारिश्रमिक और पेन्शनें

1. भारत सरकार द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का राष्ट्रिक है, यूनाइटेड किंगडम में सरकारी कार्य करने के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में, भुगतान किया गया, पेन्शन से भिन्न, पारिश्रमिक यूनाइटेड किंगडम से कर से मुक्त होगा।

2. यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रिक है, भारत में सरकारी कार्य करने के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में, भुगतान किया गया, पेन्शन से भिन्न पारिश्रमिक भारतीय कर से मुक्त होगा।

3. संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को, उस सरकार के लिये की गयी सेवाओं के संबंध में भुगतान की गयी किसी भी प्रकार की पेन्शन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

4. इस अनुच्छेद के उपबंध, किसी व्यापार अथवा, कारोबार के संबंध में की गयी सेवाओं के लिये भुगतान किये गये पारिश्रमिक अथवा, पेन्शन पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी

1. ऐसे व्यक्ति पर, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का निवासी था और जो उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित मुख्य प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से उपस्थित है :

- (क) उस अन्य संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय अथवा अन्य अधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्ययन करने के लिये ; अथवा
- (ख) कोई व्यवसाय करने अथवा व्यावसायिक विशेषज्ञता के लिये उसे प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित प्रशिक्षण पाने के लिये ; अथवा
- (ग) किसी सरकारी, शैक्षिक, धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा शैक्षिक संगठन से अनुदान भत्ता, अथवा पुरस्कार पाने वाले, जो रूप में अध्ययन करने के लिये अथवा अनुसंधान करने के लिये ;

उस अन्य राज्य द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कर नहीं लगाया जायेगा :

- (i) उसके निर्वाह शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये बिदेशों से प्राप्त धन ;
- (ii) अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार ; और
- (iii) उस अन्य संविदाकारी राज्य में की गयी वैयक्तिक सेवाओं से हुई आय (किसी मार्टीकल्ड क्लर्क अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण पा रहा हो, उस व्यक्ति अथवा भागीदारिता के लिये, जिसके साथ वह पार्टनरशिप है अथवा जो प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, की गई किसी सेवा से भिन्न सेवा), जो किसी वित्तीय वर्ष में 750 पाँड स्टर्लिंग या भारतीय मुद्रा में उसके बराबर रकम से अधिक नहीं हो।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत दी गई छूटें केवल ऐसी समयावधि के लिए ही लागू रहेंगी जो उक्त यात्रा के प्रयोजनार्थ उचित रूप से अथवा प्रमाणों द्वारा अपेक्षित हों, परन्तु किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लाभ 5 से अधिक वर्षों के लिए नहीं मिलेगा।

3. ऐसे व्यक्ति पर, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का निवासी था और जो उस अन्य राज्य में 12 मास से अधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से, प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के कर्मचारी के रूप में अथवा संविदा के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य प्रयोजन के लिए उपस्थित है :

- (क) प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य के उस निवासी से भिन्न किसी व्यक्ति से तकनीकी, व्यावसायिक अथवा कारोबार सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करने के लिए ; अथवा
- (ख) उस अन्य संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय अथवा अन्य अधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्ययन करने के लिए ;

अन्य संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं से हुई उसकी आय पर, जो 1500 पाँड स्टर्लिंग अथवा भारतीय मुद्रा में उसके बराबर रकम से अधिक नहीं हो, उस अन्य संविदाकारी राज्य द्वारा उस अवधि के लिए लगाया जाएगा।

4. ऐसे व्यक्ति पर, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का निवासी था और जो उस अन्य राज्य में 12 मास से अधिक अवधि के लिए, अन्य संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में

भाग लेने वाले के रूप में, प्रशिक्षण, अनुसंधान प्रयत्न अध्ययन के मुख्य प्रयोजन के लिए, अस्थायी रूप से निवासी है, प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा उनके निवास, प्रशिक्षण, अनुसंधान प्रयत्न अध्ययन के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतान के सम्बन्ध में उस अन्य संविदाकारी राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 21

अध्यापक

1. ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संविदाकारी राज्य में वहाँ के किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य माध्यम प्राप्ति शैक्षणिक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान-कार्य करने के प्रयोजनार्थ अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए दौरा करता है, और जो उस दौर के तत्काल पूर्व अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी था, ऐसे अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य के लिए प्राप्त होने वाले किसी पारिश्रमिक पर, जिस तारीख से वह पहली बार उक्त प्रयोजनार्थ उस राज्य का दौरा करता है, उस तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए, प्रयोज्य संविदाकारी राज्य द्वारा कर में छूट दी जाएगी।

2. यह अनुच्छेद, अनुसंधान-कार्य में प्राप्त होने वाली आय पर केवल उस राज्य में लागू होगा यदि ऐसा अनुसंधान-कार्य व्यक्ति द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में शुरू किया गया हो, कि मूलतः किसी अन्य निजी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए।

अनुच्छेद 22

बाहरे कंपनियों का परिहार

1. यूनाइटेड किंगडम में बाहरे किसी राज्य क्षेत्र में देय कर को यूनाइटेड किंगडम के प्रति जमा मानने की स्वीकृति देने से सम्बन्धित यूनाइटेड किंगडम के कानून के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे) :

(क) भारत के कानूनों के अन्तर्गत और उस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा, भारत के भीतर स्रोतों से प्राप्त लाभों, आय अथवा प्रभाष्य लाभों (जिनमें, किसी भाषाण के मामले में, जिन लाभों में से लाभार्थ अदा किया जाता है उनके सम्बन्ध में देय कर की रकम शामिल नहीं है पर देय भारतीय कर की समान लाभों, आय अथवा प्रभाष्य लाभों के जिस संघर्ष में भारतीय कर की संगणना की जाती है उस संघर्ष में संगणित यूनाइटेड किंगडम कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(ख) किसी कम्पनी द्वारा, जो भारत की निवासी हो, किसी ऐसी कम्पनी को जो यूनाइटेड किंगडम की निवासी हो और जिसके नियंत्रण में लाभार्थ की अदायगी करने वाली कम्पनी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कम से कम 10 प्रतिशत सहाधिकार हो, उसके द्वारा प्रयुक्त किसी लाभार्थ के सम्बन्ध में (किसी ऐसे भारतीय कर के अभाव में इसके लिए इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के उपबन्धों के तहत जमा की स्वीकृति दी जा सकती हो) जमा की जाने वाली रकम में ऐसे लाभों के बारे में, जिसमें से ऐसे लाभार्थ की अदायगी की गई हो, कम्पनी द्वारा देय भारतीय कर की हिसाब में लिया जायेगा।

परन्तु यह पैराग्राफ किसी कम्पनी पर लागू नहीं होगा जो यूनाइटेड किंगडम की निवासी हो और जिस कानून अभिसमय 1975 की अनुसूची 9 के प्रयोजनार्थ यथा परिभाषित एक नोन कम्पनी हो।

4. भारत के बाहरे किसी राज्य क्षेत्र में देय कर की भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकृति देने के सम्बन्ध में भारत के कानून

के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे), यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के तहत और इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के भीतर स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में, जिन पर भारत में तथा यूनाइटेड किंगडम दोनों में कर लगाया गया हो, भारत के किसी निवासी द्वारा देय यूनाइटेड किंगडम कर की रकम को उस आय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकृति दी जायेगी किन्तु उतनी रकम पर स्वीकृति दी जायेगी जितना प्रतिशत अनुपात उस भारतीय कर से अधिक नहीं हो जो भारतीय कर के लिए प्रभाष्य सम्पूर्ण आय के रूप में एक भाग हो। किसी भी हालत में यूनाइटेड किंगडम कर के लिए जमा की स्वीकृति, कम्पनियों की प्रतिनिधि आय पर अनिश्चित आय कर के प्रति नहीं दी जायेगी।

इस पैराग्राफ में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के निम्ने, जहाँ पर भारत का निवासी एक ऐसी कम्पनी हो जिसके द्वारा अतिकर देय हो वहाँ पर भारतीय कर के प्रति मंजूर की जाने वाली जमा की स्वीकृति, भारत में कम्पनी द्वारा देय आय-कर के प्रति पहली बार दी जायेगी, और देय रकम के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अतिकर के प्रति स्वीकृति दी जायेगी।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए "देय भारत कर" शब्दों में निम्नलिखित के अन्तर्गत ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जाएगी जो भारतीय कर के रूप में देय होती यदि निम्नलिखित के तहत उस वर्ष के लिए स्वीकृत कर योग्य आय प्रयत्न कोई छूट अथवा कटौती की संगणना में घटौती की रकम शामिल नहीं हुई होती :-

(क) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4) 10(4क) 10(6) (vii-क), 10(15)(iv), 32क, 33क, 35क, 35ग, 80ज, 80जा और 80ड, जहाँ तक कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू थी और उक्त तारीख से उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन हुआ हो जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; अथवा

(ख) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर की ऐसी छूट अथवा कटौती मंजूर करने के लिए बाद में किए जाएं जिनके बारे में संविदाकारी राज्यों के सश्रम प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि उनके स्वरूप में उस हालत में काफी समानता है यदि उसमें बाद में संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिसमें उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

परन्तु यूनाइटेड किंगडम के कर में राहत, किसी स्रोत से प्राप्त आय के सम्बन्ध में इस पैराग्राफ की वजह से उस स्थिति में नहीं दी जाएगी यदि आय का सम्बन्ध उस स्रोत के बारे में यूनाइटेड किंगडम के निवासी को अथवा भारत के निवासी को, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय कर में जिस अवधि से छूट अथवा घटौती पहली बार दी गई हो उस अवधि के बाद 10 बित्तीय वर्षों से अधिक की शुरू होने वाली अवधि से हो।

4. ऐसी आय को, जिस पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगता हो, उस संविदाकारी राज्य में अन्य आय पर आवय किये जाने योग्य कर की दर की संगणना में हिसाब किताब में लिया जा सकता है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्थायित्व में लाभों, आय तथा प्रभाष्य अभिवृत्तियों को, जिन पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, उस अन्य संविदाकारी राज्य में स्रोतों से उत्पन्न हुआ माना जायेगा।

6. जहाँ पर लाभों को, जिन पर किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस राज्य में कर लगाया गया हो, अन्य राज्य के किसी उद्यम

के आर्भों में भी शामिल किया गया हो और इस प्रकार वे शामिल किए गए लाभ ऐसे लाभ हों जो अन्य राज्य के उस उद्यम में उस हानि में उद्भूत हुए हों। यदि उद्यमों के बीच ऐसी शर्तें निर्धारित होतीं जो दूसरे के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले उद्यमों के बीच निर्धारित की गई होतीं, ऐसे मामले में दोनों उद्यमों के लाभों में समाविष्ट रकम को, इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, प्रथमोक्त राज्य के उद्यम के अन्य राज्य में किसी स्त्रोत से आय के रूप में माना जायेगा और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 अथवा पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के तहत तदनुसार राहत दी जायेगी।

7. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार" शब्दों में ऐसे कर समाविष्ट होंगे जो इस अभिसमय के विषय क्षेत्र हैं और जो अभिसमय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गई आय पर लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद 23

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उस सम्बन्धित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भार-पूर्ण हों, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्य-में, उन्हीं परिस्थितियों में अथवा वैसी ही स्थितियों के अन्तर्गत प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों। इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को, एक स्थायी संस्थान के उन लाभों को प्राप्त करने से रोका जाए, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, पूर्वोक्तलिखित राज्य में कर की उस दर पर, प्राप्त करता है जो पूर्वोक्तलिखित संविदाकारी राज्य के एक वैसे ही उद्यम के लाभों पर प्रवृत्त कर की दरों की अपेक्षा अधिक हों और इसका अर्थ, इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 4 के उपबन्धों के प्रतिकूल भी नहीं लगाया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के नागरिकों की, कारागारों के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की वैयक्तिक छूटें, राहतें तथा भट्टीयों प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्सम्बन्धी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भार-पूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर लागू होती है, अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद का अर्थ वे कर हैं जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 24

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो

कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, यह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह इस राज्यों के राष्ट्रीय कानूनो द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूगरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उगभारने की हल करने का प्रयास करेगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।

4. पूर्वाक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अन्तर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जो ऐसी सूचना और दस्तावेज हो जो प्रशासन की सामान्य स्थिति में उनके अपने अपने कराधान कानूनों के अन्तर्गत उनके पास हो) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबन्धों की लागू करने के लिये अथवा छोटे-बड़ी की रोकथाम के लिए अथवा ऐसे करों के सम्बन्ध में कानूनी परिहार के विरुद्ध तात्कालिक उपबन्धों के प्रशासन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जाएगा परन्तु उसे ऐसे करों के सम्बन्ध में जो इस अभिसमय का विषय है कर-निर्धारण कार्य, वसूली कार्य, प्रवर्तन अथवा अभियोजन की कार्यवाही से सम्बन्धित व्यक्तियों (जिसमें व्यापारिक अथवा प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) के समक्ष प्रकट किया जा सकता है। ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यापार, कारोबार, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा कोई व्यापार प्रक्रिया प्रकट होती हो।

अनुच्छेद 26

राजनयिक तथा नौसली अधिकारी

1. इस अभिसमय से, राजनयिक अथवा नौसली अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त नौसली विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. अनुच्छेद 4 (नौसली अधिकार) के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई व्यष्टि जो किसी संविदाकारी राज्य के ऐसे राजनयिक, नौसली अथवा स्थायी शिष्ट-मण्डल का सदस्य है जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है और जो उस दूसरे राज्य में केवल तब कर लगाये जाने योग्य है यदि वह उस राज्य के स्त्रोतों से आय प्राप्त करता है तो उसे इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं समझा जाएगा।

अनुच्छेद 27

प्रवर्तन

संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस अभिसमय को लागू करने के लिए उसकी विधि द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा किये जाने

के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह अधिसूचना, इस अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख में लागू होगा और उनके बाद।

(क) यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और नार्वेन आयरलैण्ड में:

(i) जिस कैलेंडर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना दी गयी हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कैलेंडर वर्ष में 6 अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर तथा पूंजीगत लाभ के सम्बन्ध में;

(ii) जिस कैलेंडर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना दी गयी हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निगम कर के सम्बन्ध में;

(iii) जिस कैलेंडर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना दी गयी हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी भी प्रभावी अवधि के लिए पेट्रोलियम सम्बन्धी राजस्व कर के सम्बन्ध में;

(iv) जिस कैलेंडर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना दी गयी हो, उसके अगले परवर्ती वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाले विकास मूल्य की बसूल की गयी किसी भी राशि के लिए विकसित भूमि-कर के सम्बन्ध में;

(ख) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना दी गयी हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के सम्बन्ध में लागू होगा।

(3) जिस कैलेंडर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी भी प्रभावी अवधि के लिए, पेट्रोलियम राजस्व कर के सम्बन्ध में;

(4) जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाले विकास मूल्य की बसूल की गयी राशि के लिए, विकसित भूमि-कर के सम्बन्ध में; और

(ब) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी राजस्व वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के सम्बन्ध में।

जिसके माध्यम से, इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा अधिवक्त प्राधिकृत अधिकृत अधिकारियों ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में अप्रैल 1981 के 16 वें दिन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में किया गया, इसके दोनों पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे। दोनों पाठों में शिथिल होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत सरकार की ओर से:

जी० रामचन्द्रन

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्वेन आयरलैण्ड की सरकार की ओर से:

जे० ए० ग्रामसन

[स० 301/6/75-एफ० टी० डी०]

र०/र०० खोला, संयुक्त सचिव

अनुच्छेद 28

समाप्ति

यह अधिसूचना उग समय तक लागू रहेगा जब तक कि साक्षिकाती राज्यों में से एक राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। संविधानकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, अधिसूचना के लागू होने की तारीख से कम वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः महीने पहले राजनयिक माध्यम से समाप्ति का नोटिस देकर अधिसूचना को समाप्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति में यह अधिसूचना।

(क) यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्वेन आयरलैण्ड में:

(1) जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में 6 अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर तथा पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में;

(2) जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, निगम कर के सम्बन्ध में;

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1981

INCOME-TAX

G.S.R. 612(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains has come into force on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required by their respective laws, as required by Article 27 of the said Convention.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS

The Government of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains:

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes covered

(1) The taxes which are the subject of this Convention are:

(a) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

- (i) the income tax;
 - (ii) the corporation tax;
 - (iii) the capital gains tax;
 - (iv) the petroleum revenue tax; and
 - (v) the development land tax;
- (hereinafter referred to as "United Kingdom tax");

(b) in India:

- (i) the income-tax and any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);
- (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including any area outside the territorial sea of the United Kingdom which in accordance with international law has been or may hereinafter be designated, under the laws of the United Kingdom concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of the United Kingdom with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised;
- (b) the term "tax" means United Kingdom tax or Indian tax, as the context requires;

(c) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(d) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the United Kingdom or India, as the context requires;

(e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "competent authority" means, in the case of the United Kingdom the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative, and in the case of India the Central Government in the Department of Revenue;

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(j) the term "Government" means the Government of a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof. In relation to the United Kingdom, the term "political sub-division" shall include Northern Ireland.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 4

Fiscal domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident

of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent establishment

For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) premises used as a sales out let or for receiving or soliciting orders;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (i) an installation or structure used for the exploration of natural resources;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period or more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise. However, this provision shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purpose or purposes other than the purposes specified in this paragraph.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 of this Article applies shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if :

- (a) he has and habitually exercises in that State, an authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such an agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise (or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it) he shall not be considered to be an agent of an independent status for the purposes of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other

ARTICLE 6

Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

- (2) (a) The term "immovable property" shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.
- (b) The term "immovable property" shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In so far as it has been customary in a Contracting State according to its law to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall

preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

4. (a) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses of the enterprise which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including only those executive and general administrative expenses incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

Provided that where the law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated imposes a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed, and that restriction is relaxed or overridden by any convention between that Contracting State and a third State which enters into force after the date of entry into force of this Convention, the competent authority of that Contracting State shall notify the competent authority of the other Contracting State of the terms of the corresponding paragraph in the Convention with that third State immediately after the entry into force of that Convention and, if the competent authority of the other Contracting State so requests, the provisions of this sub-paragraph shall be amended by protocol to reflect such terms.

- (b) However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

Air transport

1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of participation in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purposes of this Article :

- (a) interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and

(b) the term "operation of aircraft" shall include transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of aircraft owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

ARTICLE 9

Shipping

1. Income of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article such income may be taxed in the other Contracting State from which it is derived provided that :

- (a) the income is in respect of any one or more of the first ten fiscal years for which this Convention has effect ;
- (b) the tax chargeable on that income shall be 50 per cent of the tax which would have been chargeable in the absence of this Convention in respect of the income for the first five fiscal years for which this Convention has effect and 25 per cent of such tax for the next following five years.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not apply to income from journeys between places which are situated in a Contracting State.

4. For the purposes of this Article, income from the operation of ships includes income derived from the rental on a bareboat basis of ships if such rental income is incidental to the income described in paragraph 1 of this Article.

5. Notwithstanding the provisions of Article 7 (Business profits), the provisions of paragraphs 1 and 2 and 5 of this Article shall likewise apply to income of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise.

6. The provisions of this Article shall apply also to income derived from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

7. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or containers owned and operated by the enterprise shall be taxed only in that State if either the income from the operation of the alienated ships or containers was taxed only in that State, or the ships or containers are situated outside the other Contracting State at the time of the alienation.

ARTICLE 10

Associated enterprises

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State ; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State ;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations

which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 11

Dividends

1. (a) A dividend paid by a company which is a resident of the United Kingdom to a resident of India may be taxed in India.
- (b) Where under paragraph 2 of this Article, a resident of India is entitled to a tax credit in respect of that dividend, tax may also be charged in the United Kingdom and according to the laws of the United Kingdom on the aggregate of the amount or value of the dividend and the amount of the tax credit, at a rate not exceeding 15 per cent.
- (c) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, a dividend derived from a company which is a resident of the United Kingdom by a resident of India, who is the beneficial owner of that dividend shall be exempt from any tax in the United Kingdom which is chargeable on dividends.
2. A resident of India who receives a dividend from a company which is a resident of the United Kingdom shall, subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and provided he is the beneficial owner of the dividend, be entitled to the tax credit in respect of that dividend which an individual resident in the United Kingdom would have been entitled to had he received that dividend, and to the payment of any excess of that tax credit over his liability to United Kingdom tax.
3. Paragraph 2 of this Article shall not apply where the beneficial owner of the dividend is a company which either alone or together with one or more associated companies controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend. For this purpose two companies shall be deemed to be associated if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third company.
4. A dividend paid by a company which is a resident of India to a resident of the United Kingdom may be taxed in the United Kingdom. The dividend may also be taxed in India but, where the dividend relates in whole or in part to a new contribution, the Indian tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividend attributable to the new contribution.
5. The preceding paragraphs of this Article shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividend is paid.
6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 or, as the case may be, paragraph 4 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividend, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, a permanent establishment or fixed base with which the holding by virtue of which the dividend is paid is effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services), as the case may be, shall apply.
7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

8. As used in this Article the term "dividend" means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights treated in the same manner as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident and any other item (other than interest which falls within the provisions of Article 12) treated as a dividend or distribution under that law.

9. As used in paragraph 4 of this Article the term "new contribution" means any share capital, other than bonus shares, issued after the date of entry into force of this Convention by a company which is a resident of India, and beneficially owned by a resident of the United Kingdom.

ARTICLE 12

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, provided that where the resident of the other Contracting State is the beneficial owner of the interest and it is paid in respect of a loan or debt first created after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article :

- (a) where the interest is paid to a bank carrying on a bona fide banking business which is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest ;
- (b) where the interest is paid to the Government of one of the Contracting States or a political subdivision or local authority of that State or the Reserve Bank of India, it shall not be subject to tax by the State in which it arises.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services), as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment or fixed base then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and some other person, the amount of the interest paid

exceeds for whatever reason the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

Royalties and fees for technical services

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State; provided that where the royalties or fees for technical services are paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof and they are paid in respect of a right or property which is first granted, or under a contract which is signed, after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind including rentals received as a consideration for the use of, or the right to use :

- (a) any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process ;
- (b) industrial, commercial or scientific equipment, or information concerning industrial, commercial or scientific experience ;
- (c) any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematographic films, and films or tapes for radio or televisions broadcasting ;

but does not include royalties or other amounts paid in respect of the operation of mines or quarries or of the extraction or removal of natural resources.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15 (Independent personal services), in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services), as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make the payments was incurred and the payments are borne by that permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid exceeds for whatever reason

the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 14

Capital gains

Except as provided in Articles 8 (Air transport) and 9 (Shipping) of this Convention, each Contracting State may tax capital gains in accordance with the provisions of its domestic law.

ARTICLE 15

Department personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if :

- (a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 90 days in the relevant fiscal year ; or
- (b) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities ;

but in each case only so much of the income as is attributable to those services.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

Department personal services

1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' fees), 18 (Artistes and athletes), 19 (Governmental remuneration and pensions), 20 (Students and trainees) and 21 (Teachers), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of the United Kingdom in respect of an employment exercised in India shall not be taxed in India if :

- (a) he is present in India for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant fiscal year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of India; and
- (c) the remuneration is not deductible in computing the profits of an enterprise chargeable to Indian tax.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of India in respect of an employment exercised in the United Kingdom shall not be taxed in the United Kingdom if :

- (a) he is present in the United Kingdom for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant fiscal year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the United Kingdom; and

- (c) the remuneration is not deductible in computing the profits of an enterprise chargeable to United Kingdom tax.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad on a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State of which the person deriving the profits from the operation of the ship or aircraft is a resident.

ARTICLE 17

Directors' fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

Artists and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Independent personal services) and 16 (Department personal services), income derived by entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artists and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income arising from personal activities as such exercised in a Contracting State by an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business profits), 15 (Independent personal services) and 16 (Department personal services), be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including a political subdivision or local authority of that other State.

ARTICLE 19

Governmental remuneration and pensions

1. Remuneration, other than a pension, paid by the Government of India to any individual who is a national of India in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the United Kingdom shall be exempt from United Kingdom tax.

2. Remuneration, other than a pension, paid by the Government of the United Kingdom to any individual who is a national of the United Kingdom in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in India shall be exempt from Indian tax.

3. Any pension paid by the Government of a Contracting State to any individual in respect of services rendered to that Government shall be taxable only in that Contracting State.

4. The provisions of this Article shall not apply to remuneration or pension in respect of services rendered in connection with any trade or business.

ARTICLE 20

Students and trainees

1. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of :

- (a) studying at a university or other accredited or recognised educational institution in that other Contracting State; or

- (b) securing training required to qualify him to practise a profession or a professional speciality; or
(c) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation;

shall not be subject to tax by that other Contracting State in respect of :

- (i) gifts from abroad for the purposes of his maintenance, education, study, research or training;
(ii) the grant, allowance, or award; and
(iii) income from personal services rendered in that other Contracting State (other than any rendered by an article clerk or other person undergoing professional training to the person or partnership to whom he is article clerk or who is providing the training) not exceeding the sum of 750 pounds sterling or its equivalent in Indian currency during any fiscal year.

2. The exemptions under paragraph 1 of this Article shall only extend for such period of time as may be reasonably or customarily required for the purpose of the visit, but in no event shall any individual have the benefit of paragraph 1 of this Article for more than 5 years.

3. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for a period not exceeding 12 months, as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of :

- (a) acquiring technical, professional or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State; or
(b) studying at a university or other accredited or recognised educational institution in that other Contracting State;

shall not be subject to tax by that other Contracting State on his income from personal services performed in the other Contracting State for that period in an amount not exceeding 1,500 pounds sterling or its equivalent in Indian currency.

4. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for a period not exceeding 12 months as a participant in a programme sponsored by the Government of the other Contracting State, for the primary purpose of training, research or study, shall not be subject to tax by that other Contracting State in respect of payments made by the Government of the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, training, research, or study.

ARTICLE 21

Teachers

1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college or other recognised educational institution in that State, and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from tax by the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date he first visits that State for such purpose.

2. This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

ARTICLE 22

Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof) :

- (a) Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within India (excluding, in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Indian tax is computed.
- (b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Indian tax for which credit may be allowed under the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph) the Indian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

Provided that this paragraph shall not apply to a company which is a resident of the United Kingdom and is a Petroleum Company as defined for the purposes of Schedule 9 to the Oil Taxation Act 1975.

2. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof), the amount of United Kingdom tax payable, under the laws of the United Kingdom and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within the United Kingdom which has been subjected to tax both in India and the United Kingdom shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax. In no case shall credit for United Kingdom tax be given against the additional income-tax on undistributed income of companies.

For the purposes of the credit referred to in this paragraph, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

3. For the purposes of paragraph 1 of this Article the term 'Indian tax payable' shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under

- (a) sections 10(4), 10(4A), 10(6) (vii), 10(15) (iv), 32A, 33A, 35B, 35CC, 80HH, 80J and 80K of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Convention or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (b) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

Provided that relief from United Kingdom tax shall not be given by virtue of this paragraph in respect of income from any source if the income relates to a period starting

more than 10 fiscal years after the exemption from, or reduction of, Indian tax is first granted to the resident of the United Kingdom or to the resident of India, as the case may be, in respect of that source.

4. Income which in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article profits, income and chargeable gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with the provisions of this Convention shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.

6. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise of the other State and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the other State if the conditions made between the enterprises had been those which would have been made between enterprises dealing wholly independently with each other, the amount included in the profits of both enterprises shall be treated for the purposes of this Article as income from a source in the other State of the enterprise of the first-mentioned State and relief shall be given accordingly under the provisions of paragraph 1 or paragraph 2 of this Article.

7. For the purposes of this Article the term "in accordance with the provisions of this Convention" shall include taxes which are the subject of this Convention and imposed on income not expressly mentioned in the Convention.

ARTICLE 23

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 4 of Article 7 of this Convention.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individual not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to individuals who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 24

Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result

or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 25

Exchange of Information

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information and documents which are at their disposal under their respective taxation laws and obtained in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of this Convention. Any information or documents so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of taxes which are the subject of this Convention. No information or documents shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or any trade process.

ARTICLE 26

Diplomatic and consular officials

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 4 (Fiscal domicile), an individual who is a member of the diplomatic, consular or permanent mission of a Contracting State which is situated in that other Contracting State and who is subject to tax in that other State only if he derives income from sources therein, shall not be deemed to be a resident of that other State for the purposes of this Convention.

ARTICLE 27

Entry into force

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;

(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;

(iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;

(iv) in respect of development land tax, for any realised development value accruing on or after 1 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;

(b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

ARTICLE 28

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through the diplomatic channel, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of ten years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the notice is given;

(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice is given;

(iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice is given;

(iv) in respect of development land tax, for any realised development value accruing on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice is given; and

(b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereby by their respective Governments, have signed this Convention.

Done on this 16th Day of April, 1981 in New Delhi on two original copies each in the Hindi and English languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT
OF INDIA:

G. RAMACHANDRAN

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND:

J. A. THOMSON

[No. 501/6/75-FTD]

R. R. KHOSLA, Jt. Secy.

